

कारखाना अधिनियम 1948

मजदूरी सहित वार्षिक अवकाश  
(Annual leave with wages)

कारखाना अधिनियम 1948 के अध्याय में 8 में धारा 78 से 84 में मजदूरी सहित वार्षिक अवकाश से संबंधित प्रसवधानों का वर्णन है, जो निम्नलिखित हैं-

## (i) प्रस्तुत अध्याय का क्षेत्र (Application of the chapter)

यदि श्रमिकों को किसी कानून के अधीन या किसी सम-कर्मों के अन्तर्गत अवकाश के विषय में कोई अधिकार मिलता है तो इस अध्याय का उन श्रमिकों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस अध्याय के प्रावधान किसी भी श्रेणी वर्कमैन में काम करने वाले श्रमिकों पर लागू नहीं होंगे।

## (ii) मजदूरी सहित वार्षिक अवकाश (Annual leave with wages)

ऐसे प्रत्येक श्रमिक जिन्होंने कैलेंडर वर्ष में किसी कारखाना में 240 दिन या उससे अधिक अवधि के लिए काम किया है तो आगामी कैलेंडर वर्ष में मजदूरी सहित वार्षिक अवकाश का अनुमति दी जायेगी। जिसकी गणना निम्न रूप में की जायेगी।

(a) वयस्क श्रमिकों के लिए उनके द्वारा किए गए काम के प्रति 20 दिन पर 1 दिन के हिसाब से।

(b) बालक श्रमिकों के लिए उनके द्वारा दिये गये काम के प्रति 15 दिन पर 1 दिन के हिसाब से।

240 दिनों की गणना में निम्न दिनों की भी गिना जायेगा

- (a) कामवर्ती किसी स्थायी आदेशों के तरह स्वीकृत लाभ के दिन
- (b) महिला श्रमिकों की प्रत्येक 12 सप्ताह का मातृत्व लाभ के दिन
- (c) पूर्व के वार्षिक अर्जित अवकाश की अगामी वर्ष में उपभोग के दिन

वार्षिक अर्जित अवकाश में उन समस्त छुट्टियों को शामिल नहीं किया जाएगा जो ऐसे अवकाश के बीच अथवा पहले या बाद में पड़ती हैं। यदि किसी श्रमिक की सेवा 1 जनवरी या बाद में शुरू होती है तो उसे शेष दिनों के 2/3 दिनों के आधार पर अर्जित अवकाश का लाभ दिया जायेगा।

यदि किसी कैलेंडर वर्ष के बीच किसी श्रमिक को पद मुक्त या पदच्युत कर दिया जाता है या सेवाकाल में ही उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसे या उसके उत्तराधिकारी अथवा नामांकित के निर्धारित दर पर मजदूरी प्राप्त करने का अधिकार होगा। नौकरी छोड़ने वाले श्रमिकों को भी अवकाश के एपोज में मजदूरी देना होगा। छुट्टियों की गणना करते समय आधी दिन या आधी से अधिक दिन को पूरा दिन माना जायेगा। एक वयस्क श्रमिक वार्षिक अर्जित अवकाश को अधिक से अधिक 30 दिन तक संचित कर सकता है तथा एक बालक श्रमिक वार्षिक अर्जित अवकाश को अधिक से अधिक 40 दिन तक संचित कर सकता है।

सामान्य सेवा में नियुक्त श्रमिकों से वार्षिक अर्जित अवकाश हेतु कम से कम 15 दिन पूर्व प्रबंधक को

प्रार्थना पत्र देना अनिवार्य है तथा लोकोपयोगी सेवा में अवकाश लेने हेतु कम से कम 30 दिन पूर्व प्रार्थना पत्र देना अनिवार्य है।

परन्तु बीमारी की दशा में वार्षिक अर्जित अवकाश हेतु उपरोक्त शर्तों में छूट दिया गया है। किसी भी वर्ष में अधिक से अधिक तीन बार ही अवकाश लिया जा सकता है। उपर्युक्त योजना को मूचना कारखाना में स्पष्ट भाषा और सुविधाजनक स्थानों पर प्रकाशित करना होगा।

(iii) अवकाश की अवधि की मजदूरी (wages during leave period)

यदि कोई श्रमिक अधिनियम की धारा 78 या 79 के अन्तर्गत मजदूरी सीहत अवकाश प्राप्त करता है, तो उसे अवकाश की अवधि की मजदूरी पूर्ण औरसत दैनिक मजदूरी के बराबर देय होगी। इसमें अतिरिक्त समय की मजदूरी (Overtime wages) तथा बोनस शामिल नहीं होगी, किन्तु महंगाई भत्ता तथा रियायती दर पर मिलने वाले लाभों का एकदम मूल्य सम्मिलित होगा। रियायती दर पर लाभ एक आदर्श परिवार के आधार पर दिया जाता है, जिसमें श्रमिक उसकी पत्नी तथा 14 वर्ष से कम आयु वाले दो बच्चों को अर्थात् कुल मिलकर 3 वयस्क उपयोगी इकाइयाँ। इस संबंध में राज्य सरकार को नियम बनाने का अधिकार प्राप्त है।

(iv) कुछ परिस्थितियों में अग्रिम भुगतान (payment in advance in certain cases)

वर्गिक श्रमिकों को 4 दिन या उससे अधिक और वास्तविक श्रमिक को 5 दिन या उससे अधिक मजदूरी सीहत अवकाश की अनुमति दिया जायगा। स्वीकृत अवकाश की अवस्था के लिए मजदूरी का भुगतान किया जायगा।

(V) अदात मजदूरी का चुकड़ा जाने वाले मजदूरी वसूल करने की शक्ति (Mode of recovery of unpaid wages)

इस अध्याय के अन्तर्गत नियोजिता द्वारा भुगतान नहीं की जाने वाली रकम की वसूली उसी प्रकार की जायेगी जिस प्रकार मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936 के अन्तर्गत विलम्बित मजदूरी (delayed wages) की वसूली की जाती है।

(vi) नियम बनाने का अधिकार (Power to make rules)

राज्य सरकार कारखाना के प्रबन्धकों द्वारा ऐसे शीजस्टों को रखने और उन्हें कारखाना निरीक्षकों की जांच के लिए उपलब्ध करने के निर्देश देने सम्बन्धी नियम बना सकती है।

(vii) कारखाना को छूट देने का अधिकार (Power to exempt factories)

राज्य सरकार यदि इस बात से संतुष्ट हो जाय कि किसी कारखाना में श्रमिकों पर लागू होने वाले अवकाश सम्बन्धी नियम उस अध्याय के प्रावधानों से कम अनुकूल नहीं हैं तो वह एक विधेयत आदेश द्वारा उस कारखाना को उस प्रावधान से छूट दे सकती है।